स्मार्ट सिटी का प्रहसन भी ज़ारी रहेगा

फ़रीदाबाद (म.मो.) झूठी जुमलेबाज़ी में माहिर भाजपा की केन्द्र व हरियाणा सरकार कभी स्वच्छता अभियान तो कभी स्मार्ट सिटी का अभियान चलाने की नौटंकी तो सदैव करती रहेंगी पर धरातल पर कभी कुछ करेंगी नहीं, करना इनकी नीयत भी नहीं। इन दोनों अभियानों की नौटंकी के नाम पर नये-नये टैक्स जनता पर लादने की योजनायें बनाई जा रही है; जबकि इन दोनों कामों के लिये न तो किसी अतिरिक्त फ़ंड की जरूरत है और न ही अभियानबाज़ी की।

स्मार्ट सिटी की नाट्कबाज़ी को आगे बढाते हुए दिनांक 25 सितम्बर को नगर निगम अधिकारियों द्वारा अपने सभागार में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें मौजिज शहरियों से, शहर को स्मार्ट बनाने के सुझाव मांगे गये, लेकिन बोलने किसी को नहीं दिया गया क्योंकि जो बोलता था वह नगर निगम की ही पोल खोलता था। अपनी आलोचना सुनना भला कौन पसंद करता है। इसी सेमिनार में उस सलाहकार कम्पनी का एक प्रतिनिधि भी हाजिर था जिसे भारत सरकार ने 'बेशकीमती' सलाह देने के लिये भाड़े पर रखा है।

कोई सलाहकार क्या सलाह देगा अथवा शहर के गणमान्य व्यक्ति क्या सलाह देंगे उसका तो पता नहीं, परन्तु 'मज़दूर मोर्चा' ने मुफ़्त में कई बार सलाह व सुझाव इस सरकार को दिये हैं। इसके अलावा अन्य मीडिया भी लगातार सलाह देता रहता है, जिस पर अमल करना इनके बस का नहीं क्योंकि इनकी नस-नस में भ्रष्टाचार व हरामखोरी भरी है। एक दैनिक अखबार पिछले करीब 6 माह से बाज़ारों व सड़कों पर अतिक्रमण तथा उससे लगने वाले जाम का सचित्र प्रकाशन कर रहा है। शहर के कुछ बाजारों से निगम ने अतिक्रमण हटाने का दिखावा तो किया लेकिन प्रत्येक बाज़ार में अतिक्रमण ज्यों का त्यों ज़ारी है। दस फ़ीट की दुकान वाले ने अपने सामने की 20 फ़ीट सड़क घेर कर जनता का आना-जाना दूभर कर रखा है। सड़कों पर नारियल फ़ोड़ने में व्यस्त नेताओं को गली मुहल्लों व सड़कों पर कुत्तों गायों व बन्दरों के झुंड के झुण्ड घूमते नज़र नहीं आते। एक विधायक ने तो 5 माह पूर्व इन्हें तुरन्त हटाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन सब हवा हवाई। जिसका जब दिल करता है सड़क पर तम्बू गाड़ कर बाजा बजाने लगता है, कोई पूछने वाला नहीं, सीवरों का गंदा उफ़न कर सड़कों पर फ़ैलता है तो फ़ैले, उससे सड़कें टूटती हैं तो टूटें, चार बूंद पानी बरसते ही शहर कीचड़ से भर जाता है, खुले मैनहौल में या सड़क के गड्ढे में गिर कर कोई मरता है तो मरे जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं।

संक्षेप में यदि सरकार अपनी सरकारी मशीनरी में से भ्रष्टाचार व हरामखोरी खत्म करके अपने तमाम कायदे कानूनों व नियमों आदि का सही ढंग से पालन करे और कराये तो एक या दो या सौ शहर नहीं पूरा देश ही स्मार्ट बन सकता है। बस इतना काम यह सरकार कर नहीं सकती, और बिना बात स्मार्ट-स्मार्ट का ढोल पीटे जा रही है।

सरकारी आंकड़ों द्वारा खोखले दावों के बावजूद महंगाई की मार

-जुगल किशोर गुप्ता

सरकारी आंकड़ों व केन्द्रीय वित्त मंत्री के बयानों से दावा किया गया है कि महंगाई पर काबू पा लिया गया है तथा मुद्रास्फीति दर में गिरावट आ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई माह में खुदरा महंगाई दर 3.69 प्रतिशत थी जो घटकर अगस्त माह में 3.66 प्रतिशत हो गई है। मोदी सरकार के विशेषज्ञ अर्थशास्त्री का कथन है कि यदि देश में वस्तुओं के मूल्यों में कमी आती रही तो इन्फ्लेशन की बजाए डिफलेशन आने का खतरा है जिसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ वास्तविकता यह है कि मध्यम व निम्न वर्ग के लोग महंगाई की मार से त्रस्त हैं और अपने अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करने के लिए मज़बूर हो रहे हैं।

लोगों को अपनी कमाई का काफ़ी बड़ा भाग खास सामग्री पर खर्च करना पड़ता है जो दिन प्रति दिन महंगाई के कारण बढता जा रहा है। अरहर, मूंग, उड़द, मसूर आदि दालों की कीमत में अप्रैल माह से अब तक 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। दूध, घी, मक्खन, खाद्य तेल आदि के मूल्य में भी वृद्धि हो गई है। जिन लोग़ों के घरों में पीएनजी गैस लगी है वहां गैस का मूल्य में भी बढोत्तरी हो गई है। प्याज व अन्य सब्जियों के मूल्य भी भारी मात्रा में बढ गए हैं। इस पर राजस्थान के कृषि मंत्री का कथन हास्यास्पद है कि यदि प्याज महंगे हो गए हैं तो लोग प्याज खाने बिना मर जाएंगे क्या। सब लोग जानते हैं कि गरीब लोग जो सब्जी, दाल आदि नहीं खरीद सकते, वे रोटी और प्याज खाकर अपना गुजर करते हैं। उनके लिये पौष्टिक भोजन प्राप्त करना तो एक स्वप्न मात्र सा है। स्पष्ट है कि लोग खाद्य सामग्री के खर्चे में तो कमी कर नहीं सकते क्योंकि पेट भरने के लिये यह बहुत जरूरी है।

पिछले वर्ष के मुकाबले में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के मूल्य में भारी कमी आई है जो अब आधे से भी कम हो गए हैं। परंतु इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिला है। जब क्रूड ऑयल अपने उच्चतम स्तर पर था तब फ़रीदाबाद में डीजल का भाव 57 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर था जबकि अब क्रूड ऑयल पहले के भाव से आधे से भी कम हो गया है तो भी डीजल का भाव 45 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर है। इससे स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के मूल्य में आई भारी कमी का लाभ उपभोक्ताओं को मिलने की बजाए तेल कम्पनियों व सरकार ने उठाया है। पेट्रोल व डीजल के मूल्य में आई कमी का नाममात्र लाभ भी केवल उनको मिला है जिनके पास अपने निजी बाहन है। आम लोग जो बस व ऑटो से यात्रा करते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बस में ऑटो के किराए में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि इसके बनिस्पत इनके किराए में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त ट्रक द्वारा माल ढुलाई के किराए में भी कोई कमी नहीं हुई। दूसरी तरफ़ ट्रक के किराए में भी वृद्धि हुई है, जिससे माल ढुलाई का खर्चा बढ गया और वस्तुओं के मूल्य बढ गए।

बिजली कम्पनियों द्वारा बिजली की दरों में भी वृद्धि की गई है। एक वर्ष पहले बिजली की जो प्रति यूनिट रेट थे उनमें अब 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। इसके अतिरिक्त बिजली विभाग ने उपभोक्ता के घरों में लगे हुए बिजली के पुराने मीटर बदलकर नए मीटर लगवा दिए है जो तेज चलते हैं जिनमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा यूनिट आते हैं। परिणामस्वरूप बिजली के बिल के राशि बढ जाती है। इस प्रकार बिजली विभाग की कारगुजारी के कारण लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है।

गरीब लोग अगर बिमार हो जाए तो उसके लिए इलाज कराना भी भारी हो जाता है। निजी अस्पतालों की तरफ़ तो वह अपना मूंह भी नहीं कर सकते और सरकारी अस्पताल की दुर्दशा जगजाहिर है। जीवन रक्षक दवाइयों की कीमत बढती जा रही है जिससे गरीब लोग कई बार आवश्यक दवाइयों पर खर्चा करने की बजाए देसी टोटकों पर आश्रित होने को मजबूर हो जाते हैं।

अत:सरकारी आंकड़ों की कार गुज़ारी के बावजूद लोग महंगाई की मार से बुरी तरह परेशान है और उनकी क्रयशक्ति भी कम हो रही है, जिससे कारखानों से निर्मित वस्तुओं की बिक्री में कमी हो रही है। इसके परिणामस्वरूप कारखानों के उत्पादन दर में कमी आ रही है, जो आर्थिक मंदी का द्योतक है। मंहगाई का उत्पादकों व देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अब मन्त्री अभिमन्यु चले जीएसटी समझने आस्ट्रेलिया

चंडीगढ (म.मो.) अभी महीना भी नहीं हुआ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अमेरिका से लौटे कि वित्त, कराधान, श्रम आदि अनेकों महकमों के मन्त्री अभिमन्यु चल दिये आस्ट्रेलिया की सैर पर। जहां खट्टर अमेरिकियों को यह समझाने गये थे कि वे अपने अधिक से अधिक डॉलरों को लेकर भारत में आ जायें वहीं अभिमन्यु आस्ट्रेलिया गये है जीएसटी (गुडस एवं सर्विस टैक्स) का अध्ययन करने के लिये।

विदित है कि जीएसटी लागू करने की योजना भारत में करीब पिछले दस वर्षों से चल रही है। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के राज में इसे भाजपा ने लागू नहीं होने दिया था तो अब भाजपानीत एनडीए के राज में कांग्रेस इनके राह में रूकावट बनी खड़ी है। पता नहीं यह जीएसटी कब लागू होगा, होगा भी या नहीं, लेकिन अभिमन्यु को इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी लगा। वैसे आमतौर पर मन्त्रियों को राजनीतिक पैंतरेबाजियों और उठापटक से ही फुर्सत नहीं होती जो वे कोई सरकारी काम-काज करें। इसके लिये तो अफ़सरशाहों की पूरी फ़ौज तैनात है। इसलिये किसी टैक्स व्यवस्था का कोई अध्ययन करना ही है तो इन अफ़सरों को करने दो जिन्होंने वास्तव में इसे लागू करना है।

वैसे अध्ययन करना अच्छी बात होती है। लेकिन भारत में लगने वाले किसी टैक्स का अध्ययन इतनी दूर देश आस्ट्रेलिया में ही क्यों होता है, समझ से बाहर है। जबकि दसियों साल से उछल रहे इस जीएसटी मुद्दे का सारा मसौदा तो भारत में ही उपलब्ध है और फ़िर भी यदि कुछ दूसरे किसी देश से चाहिये तो वह सब आजकल बड़ी सरलता से इंटरनेट पर उपलब्ध है।

सर्वविदित है कि अध्ययन, ट्रेनिंग, मीटिंग आदि तो जनता के पैसे पर घूमने फ़िरने का बहाना मात्र ही होते हैं। ऐसा करने वाले मन्त्री अभिमन्यु न तो पहले हैं न आखिरी। देश के तमाम मन्त्री-संतरी इसी तरह की बहानेबाज़ी लगाकर जनता के खून-पसीने की कमाई पर ऐश करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, जब तक जनता इनके गिरेबान में हाथ डालकर हिसाब नहीं मांगेगी।

ईएसआई मेडिकल कॉलेज में डायलेसिस पीपीपी मोड़ पर?

फ़रीदाबाद (म.मो.) गत माह में दो बार विभिन्न अखबारों में ईएसआई कार्पोरेशन के अधिकारियों के हवाले से खबर छपी कि एनएच-3 स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डायलेसिस की सुविधा पीपीपी मोड पर चलाई जाने के लिये टेंडर जारी कर दिये गये हैं।

विदित है कि पीपीपी मोड में कोई प्राइवेट कम्पनी सरकारी साधनों के दम पर मोटा मुनाफ़ा लूटने का षड़यन्त्र सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से रचती है। लेकिन कोई भी कम्पनी इतनी मूर्ख नहीं हो सकती जो किसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस तरह से पैसा लगाने का जोखिम उठायेगी। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में नेफ़्रॉलॉजी का एक पूरा विभाग होता है जो डायलेसिस सेवा का संचालन व नियन्त्रण करने के साथ-साथ मेडिकल छात्रों को इस तकनीक से अवगत करा कर उन्हें ट्रेंड भी करता है।

मेडिकल कॉलेज जैसे उत्तम श्रेणी के अस्पताल बनाने की अपेक्षा, पीपीपी मोड में चिकित्सा व्यापार का धंधा चलाने का विचार ईएसआई निगम के कुछ निकृष्ट अधिकारियों के दिमाग में जरूर उछलता रहा है। लगता है उन अधिकारियों के दिमाग में भ्रष्टाचार एवं हरामखोरी के वे कीड़े अभी कुलबुला रहे हैं, जिन्हें मारना जरूरी है।

×××××××

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के 16-30 सितम्बर 2015 के अंक में राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले। आरक्षण का मुद्दा सदैव चर्चा में रहा है। जैसे-जैसे रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं और शिक्षण संस्थाओं में दाखिले की समस्या बढ रही है, वैसे-वैसे समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा आरक्षण की मांग उठाई जाती है तो दूसरी तरफ़ आरक्षण विरोधियों द्वारा तर्क दिया जाता है कि आरक्षित कोटे से आये लोगों में योग्यता व कुशलता की कमी पाई जाती है। परंतु आरक्षण विरोधी विभिन्न संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटे से दाखिले की कमी आलोचना नहीं करते क्योंकि उसमें धनाढय लोगों को मौका मिलता है और उनकी योग्यता और कुशलता पर कमी कोई सवाल नहीं उठाता। इस सबंध में 'वैश्वीकरण दौर में आरक्षण-गुजरात जला, हरियाणा में भी चिंगारी' अति महत्वपूर्ण है जिसमें इस समस्या पर सटीक चर्चा की गई है और आरक्षण के विरोध में प्रस्तुत तर्कों का सटीक तार्किक उत्तर दिया गया है।

गुजर व जाट आरक्षण के लिये तो आन्दोलन समय-समय पर चलाए जाते रहे हैं, परंतु गुजरात में हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पटेलों के लिए आरक्षण की मांग ने एक नया आयाम ला दिया है। वास्तव में यह आन्दोलन वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समाप्ति के लिए एक चाल है जिसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है।

संघ प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत ने मोदी सरकार को आरक्षण पर पुनर्विचार करने के लिये एक कमेटी बनाने का सुझाव देकर वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने का रास्ता खोल दिया है। परंतु बिहार विधान सभा चुनावों के मद्देनज़र मोदी सरकार व भाजपा ने इस सुझाव से होने वाले नुकसान पर नियंत्रण करने का प्रयास किया तथा केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था पर पुनरर्विचार करने की सरकार की कोई योजना नहीं हैं। दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया। स्पष्ट है कि यह बयान तो एक मंत्री का है जबकि मोदी सरकार में किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है। इसके अतिरिक्त मोहन भागवत के सामने स्वयं मोदी तथा पूरी मोदी सरकार घुटने टेकती है तो वहां एक मंत्री के बयान की क्या अहमियत है।

मोहन भागवत के बयान पर संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के बयान ने रविशंकर प्रसाद के दावे की पूरी पोल खोल दी है। इंद्रेश कुमार ने फ़रीदाबाद में आयोजित युवा एकता समारोह में कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से आरक्षण पर पुनर्विचार करने के लिये कमेटी बनाने का दिया गया सुझाव बिल्कुल ठीक है। संघ के पास आरक्षण का समाधान है, लेकिन वह बिहार चुनाव तक इस मामले में चुप रहेंगे। चुनाव के बाद आरक्षण का समाधान सुझाएंगे।

एक अन्य प्रकाशित लेख 'कलबुर्गी की हत्या तार्किकता का गला घोंटने का प्रयास' द्वारा स्पष्ट है कि जो भी तार्किक, उदारवादी तथा समाजसुधारक समाज में व्यस्त अंध श्रद्धा, काला जादू, मूर्ति पूजा आदि कुरीतियों की आलोचना करेंगे तो कट्टरवादी हिंदू संगठन जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, श्री राम सेना व सनातन संस्था के कार्यकर्ता उनको धमकी देने के साथ-साथ उनकी हत्या भी कर देंगे। प्रसिद्ध तार्किकतावादी नरेन्द्र दाभोलकर, सम्मानित समाज सुधारक कामरेड गोविंद पंसारे तथा प्रसिद्ध विचारक प्रोफ़ेसर एम.एस. कुलवर्गी की हत्या तथा अन्य उदारवादी व तार्किक लेखकों को दी गई धमकी से स्पष्ट है कि मोदी सरकार के राज में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है और जो भी हिंदुत्व की विचारधारा की आलोचना करेंगे उनका यही हश्र होगा। आश्चर्य है कि मोदी ने इस संबंध में ना तो कोई ब्यान दिया, ना ही इन हिन्दुत्व संगठनों व कार्यकर्ताओं के कारनामों की निंदा की और ना ही उन पर लगाम लगाई।

दिल्ली में संघ की 3 दिवसीय बैठक में मोदी समेत पूरे मंत्री मंडल द्वारा अपने अपने काम-काज का ब्यौरा देने और आगे के कार्यों के संबंध में संघ द्वारा उनको नीति देने के संबंध में स्तम्भ 'तुकी-ब-तुर्की' 'दूसरों को नसीहत, खुद मियां फ़जीहत' द्वारा मोदी के कार्यों व संघ की भूमिका का उचित विश्लेषण किया गया है। इसी स्तम्भ में सीबीआई पर केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण का पर्दाफ़ाश किया गया है। उच्चतम न्यायालय का कथन सही चरितार्थ है कि सीबीआई सरकारी तोता है जिसका इस्तेमाल केन्द्रीय सरकार अपने हित साधने में करती है।

नरेन्द्र मोदी देश अथवा विदेश जहां भी भाषण देते हैं, वे वहां यह दावा करते हैं कि उनसे पहले देश में कुछ भी नहीं था और अब वे सब समस्याओं का निदान कर रहे हैं। इस संबंध में लेख 'जब मोदी जी पैदा भी नहीं हुए' द्वारा मोदी के दावों व कथनों पर उचित व्यंग्य किया गया है।

यूपीए सरकार के दौरान अन्ना हजारे की अगुवाई में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये लोकपाल कानून बनाने के लिये आन्दोलन किया था। परंतु दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लोकपाल/लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। विधान सभा चुनाव में जिसको चाहा उसको चुनाव लड़ने के लिये टिकट दे दी। परंतु उनके बारे में कोई छानबीन नहीं की गई। परिणामस्वरूप अनेक दागी व्यक्ति चुन कर आ गये, जिससे 'आप' व केजरीवल की फ़जीहत हो रही है। पार्टी के आंतरिक लोकपाल के पद पर भी वह उस व्यक्ति को रखना चाहते हैं जो उनके निर्देशन में काम करे। लेख 'खबर दार-भ्रष्टाचार किस चिडया का नाम है जी!' में केजरीवाल से काल्पनिक साक्षात्कार के ज़रिए इस संबंध में केजरीवाल की कार्यशैली का पूरा पर्दाफ़ाश किया गया है। शेष अन्य सभी लेख भी उच्च स्तरीय व प्रशंसनीय है।

-प्रो. जुगल किशोर गुप्ता